



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1510]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2009/भाद्र 31, 1931

No. 1510]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2009/BHADRA 31, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2009

आय-कर

का.आ. 2413(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उप-धारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 1281(अ) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना में 27 जुलाई, 2007 से (अर्थात् वह तारीख जिसको स्कीम प्रवृत्त हुई थी) निम्नलिखित संशोधन करता है।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“5. ई-विवरण मध्यवर्ती की अर्हताएं—(1) ई-विवरण मध्यवर्ती के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी, अर्थात् :—

(क) उसे अधिनियम की धारा 2 के खंड (36क) में यथापरिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी या ऐसी अन्य कंपनी, जिसमें अधिनियम की धारा 2 के खंड (18) के अर्थान्तर्गत जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है और उन कंपनियों की कोई समनुषंगी होना चाहिए; या

(ख) भारत में निगमित कोई कंपनी, जिसके अंतर्गत बैंक भी हैं जिसका शुद्ध मूल्य एक करोड़ रुपए या अधिक है; या

(ग) चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या अधिवक्ताओं की कोई फर्म, यदि उसे स्थायी लेखा संख्यांक आवंटित किया गया है; या

(घ) कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या अधिवक्ता या कर विवरणी तैयारकर्ता, यदि उसे स्थायी लेखा संख्यांक आवंटित किया गया है; या

(ङ) किसी सरकारी विभाग का आहरण या संचितरण अधिकारी (सी.डी.ओ.)।

(2) ई-मध्यवर्ती के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 17 के अधीन नियुक्त निबंधक प्रमाणक प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी प्रमाणक प्राधिकारी से कम से कम श्रेणी-2 का अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र होगा।

(3) ई-मध्यवर्ती के पास ई-विवरण प्रशासक के समाधानप्रद रूप में सुरक्षा प्रक्रिया होगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निर्धारित की सूचना की गोपनीयता उचित रूप से सुरक्षित है।

(4) ई-मध्यवर्ती के पास ऐसी ई-विवरणियों के लिए, जो उसके माध्यम से फाइल की जाएंगी, समय-समय पर ई-विवरण प्रशासक द्वारा विनिश्चित किए गए अनुसार आवश्यक आर्किवल, रिट्रिवल और सुरक्षा नीति होगी।

(5) ई-मध्यवर्ती या उसका प्रधान अधिकारी किसी वृत्तिक अवचार, कपट, गबन या किसी दंडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया हो।”।

[अधिसूचना सं. 70/2009/फा. सं. 133/55/2008-टीपीएल]

विजय कुमार जैसवाल, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में, का.आ. 1281(अ) तारीख 27 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2009

INCOME-TAX

S.O. 2413(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1B) of section 139 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), *vide* S.O. 1281(E) dated the 27th July, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), with effect from 27th July, 2007 (i.e. the date on which the Scheme came into force).

2. In the said notification for para 5, the following para shall be substituted, namely :—

“5. **Qualifications of an e-Return Intermediary.**—

(1) An e-Return Intermediary shall have the following qualifications, namely :—

- (a) it must be a public sector company as defined in clause (36A) of section 2 of the Act or any other company in which public are substantially interested within the meaning of clause (18) of section 2 of the Act and any subsidiary of those companies; or
- (b) a company incorporated in India, including a bank, having a net worth of rupees one crore or more; or

(c) a firm of Chartered Accountants or Company Secretaries or Advocates, if it has been allotted a Permanent Account Number; or

(d) a Chartered Accountants or Company Secretaries or Advocates or Tax Return Preparers, if he has been allotted a Permanent Account Number; or

(e) a Drawing or Disbursing Officer (DDO) of a Government Department.

(2) the e-intermediary shall have at least class II digital signature certificate from any of the Certifying Authorities authorised to issue such certificates by the Controller of Certifying Authorities appointed under Section 17 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(3) the e-intermediary shall have in place security procedure to the satisfaction of e-Return Administrator to ensure that confidentiality of the assessee's information is properly secured.

(4) the e-intermediary shall have necessary archival, retrieval and, security policy for the e>Returns which will be filed through him, as decided by e-Return Administrator from time to time.

(5) the e-intermediary or its Principal Officer must not have been convicted for any professional misconduct, fraud, embezzlement or any criminal offence.”

[Notification No. 70/2009/F.No. 133/55/2008-TPL]

VIJAY KUMAR JAISWAL, Under Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* No. S.O. 1281(E), dated the 27th July, 2007.